Jai Maa Saraswati Gyandayini
An International Multidisciplinary-Journal
ISSN: 2454-8367 Journal home page: www.jmsjournals.in
Old UGC Approved No.: 43919, Vol. 07, Issue-III, January 2022

शासकीय योजनाओं का समाज पर प्रभाव एक समीक्षात्मक अध्ययन मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

(Impact of Government Schemes on Society An Analytical Study with Special Reference to Madhya Pradesh)

Chetna Garg[a,*] **Dr. Veena Shukla**[b,**]

[a] *Research Scholar (Sociology), Govt. Kamla Raja Girls P.G. College, Jiwaji University Gwalior, Madhya Pradesh (India).*

[b] *Professor (Sociology), Govt. Kamla Raja Girls P.G. College, Jiwaji University, Gwalior, Madhya Pradesh (India).*

KEYWORDS

शासकीय योजनाएं, सामाजिक विकास, सरकारों का दायित्व, आम–जन की स्थिति, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, औद्योगिक कांति, शैक्षणिक विकास।

ABSTRACT

मानव समाज के विकास के लिए आवश्यक है कि उसके पास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसा कि आदिकाल की बात करें तो उस समय मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से विकास धीरे–धीरे हुआ जिसे हम क्रमिक विकास भी कह सकते हैं। लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो एक तरफ से औद्योगिक क्रांति आई और दूसरी तरफ तकनीकी (टेक्नोलॉजी) में भी विकास हुआ हैं। तकनीकी विकास की वजह से समाज में नई क्रांति आई जिसमें इंटरनेट व अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लोगों में एक तरफ दूरियां भी कम हुई है, वहीं दूसरी ओर संयुक्त परिवार से एकांकी परिवार की तरफ अग्रसर हुए है, यह इसका एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। नई पीढ़ी को अगर देखें तो वह सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गजट में व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। पिछले कई दशकों में सभी परिवारों को एक साथ भोजन करते हुए एवं एक साथ हंसते मुस्कुराते देखा जाता था अब वह कहीं विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हर व्यक्ति को अब अकेलापन महसूस होने लगा है और यदि वह किसी परेशानी में पड़ जाते हैं या फिर बीमार पड़ जाते है तो अपनों को अपने पास नहीं पाते फलस्वरूप अस्पतालों में अनावश्यक खर्चों के शिकार हो जाते हैं। जिसकी वजह से लोगों को और अधिक धन कमाना पड़ता है और अधिक धन कमाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ जाती है यही एक बड़ी बजह है कि व्यक्तियों के पास समय की बड़ी कमी है। वही दूसरी ओर जनसंख्या बढ़ना और संशाधनों का सीमित होते जाना भी समाज को कही न कही महगाई की ओर धकेलना कहा जा सकता है। और मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है और ये सुविधायें आम–जन की पहुँच से दूर होती जाती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकारों के द्वारा हमेशा समाज हित में व विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक घोषणाएं की जाती है जिसमें मानव जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बनाया जा सके। लेकिन कई बार की योजनाएं मात्र घोषणा बनकर के रह जाती हैं, और कई बार यह समाज में नई क्रांति लाती है। आज शोध पत्र के माध्यम से मैं इन्हीं सभी बातों पर विचार करना चाहूंगी और समाज में शासकीय योजनाओं की क्या स्थिति है उसका एक समीक्षात्मक अध्ययन करने की कोशिश करूंगी।

प्रस्तावना

किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां की जो सरकार है उसके द्वारा समय–समय पर समाज के उत्थान के लिए और जनता को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समानता में लाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करना चाहिए। अधिकतर देशों में देखा गया है जनता के हित के लिए एवं समाज के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किया जाता है। जिसमें शिक्षा से लेकर रोजगार तक के लिए एवं अन्य प्रकार की याजनायें शामिल हैं। भारत को भी विकास की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 29 राज्यों में विभाजित किया गया है। जिससे प्रत्येक प्रदेश में सही रूप में विकास किया जा सके और वहां पर निवास करने वाली जनता को विभिन्न प्रकार के फायदे मिल सकें, जिनसे वह समाज के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहॉ की जनता को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास के साथ–साथ एवं रोग मुकत रखने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का फायदा पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए मिलता है। यदि पिछले कुछ दशकों का अवलोकन किया जाये तो बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ है।

मध्य प्रदेश की स्थिति

वर्तमान में मध्यप्रदेश में बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ पहुंच पाए और यहां के लोग समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं निम्नलिखित है जैसे कि छात्र छात्रवृत्ति स्कीम, पेंशन योजना, कृषि योजना, एवं अन्य प्रकार की स्वास्थ्य योजना संबंधी घोषणा की जाती रही है जिनका हम लोग विस्तार से अवलोकन करेंगे।

योजनाओं के प्रमुख विषय

प्रदेश की सरकारों द्वारा उन विषयों के सम्बन्ध में योजनायें बनायी जाती है जिनसे उस प्रदेश का विकास हो सके और उस प्रदेश की आम जनता को उसका फायदा मिल सके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों पर योजनायें बनायी गयी है–

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- जल जीवन मिशन
- कौशल विकास
- विद्यार्थी कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

वर्तमान में संचालित योजनायें

मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से कुछ प्रमुख योजनायें निम्नलिखित है–

1. **अग्नि सुरक्षा एंव अग्निशमन सेवा**

यह सेवा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित की जाती है जिसमें सम्पूर्ण शहर में होंने वाली अग्नि दुर्घटनाओं को रोकना और साथ हीं सही समय पर सुरक्षा एवं बचाव कार्य करना, इस योजना का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य भी किये जाते है जैसे कि पानी में डूबे हुये शवों को निकालना एवं अस्पताल पहुंचाना, विशेष अतिथियों के आगमन पर अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था करना, शहर में मनाने वाले त्यौहारों में मूर्तियों का विसर्जन एवं मोर्हरम, दीपावली, होली त्यौहारों पर अग्नि सुरक्षा का कार्य किया जाता है।[1]

2. **सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना**

यह योजना अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। जिसमें ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग/म0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा

* **Corresponding author**
E-mail: chetnagarg39@gmail.com (Chetna Garg). https://orcid.org/0000-0001-5584-3011
DOI: https://doi.org/10.53724/jmsg/v7n3.06
Received 25th Dec. 2021; Accepted 10th Jan. 2022; Available online 30th January 2022
2454-8367 /© 2022 The Journal. Published by Jai Maa Saraswati Gyandayini e-Journal (Publisher: Welfare Universe). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

आयोजित परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नानुसार धनराशि दी जाती है:–

- यदि अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाती है तो 40000 रूपये प्रदान किये जाते है।[2]
- यदि अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60000 रूपये प्रदान किये जाते है।[3]
- यदि अभ्यर्थी द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार में चयनित होने पर 50000 रूपये दिए जाते है।[4]
- यदि अभ्यर्थी द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 20000 रूपये प्रदान किये जाते है।[5]
- यदि अभ्यर्थी द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30000 रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 25000 रूपये दिए जाते है।[6]

3. मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना

यह योजना मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग द्वारा दिनॉक 01/04/2006 से प्रारम्भ की गई। इस योजना के अर्न्तगत मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या, विधवा, तलाकसुदा के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजनांतर्गत सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के आयोजन हेतु यथास्थित अधिकृत नगरीय/ग्रामीण निकाय को रूपये 3000/– प्रति कन्या के मान से प्रदान किया जाता है। तथा शेष राशि रूपये 48000/– संबंधित कन्या के बैंक बचत खाते में प्रदान की जाती है। इस प्रकार कुल राशि रूपये 51000/– प्रति कन्या प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। एवं आवश्यक शर्ते निम्नलिखित है[7]–

- कन्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों

4. युवा उद्यमी योजना

युवा उद्यमी योजना को उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग स्थापित कराने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिससे समाज के लोगों को जो समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं एवं रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, उनको समृद्ध बनाना है। यह योजना 01 अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई थी।

5. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

यह योजना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। इसके अर्न्तगत प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को सरकारी चिकित्सा संस्थाओं द्वारा इलाज किया जाता है। इसमें प्रत्येक परिवार को ₹30000 तक की सहायता प्रदान की जाती है।

6. गांव की बेटी इस योजना

यह योजना उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी गांव में निवास करने वाली एवं गांव की पाठशाला में नियमित रूप से अध्ययन करने के पश्चात 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में यदि कोई छात्रा उत्तीर्ण हो जाती है तो 500रू. प्रति माह की दर से 10 माह के लिए 5000रू. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी एवं यदि कोई छात्रा इंजीनियरिंग या मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो 750रू. प्रति माह की दर से 10 माह के लिए 7500रू. वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है।[8]

7. प्रतिभा किरण योजना

यह योजना मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शहर में निवास करने वाली एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा जिसने शहरी क्षेत्र के पाठशाला में नियमित अध्ययन करने के पश्चात 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित की है। उसको 3000रू. की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है। एवं यदि छात्रा इंजीनियरिंग तथा मेडिकल की शिक्षा के लिए प्रतिभा किरण योजना का लाभ लेना चाहे तो 7500रू. की वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है।[9]

8. जननी सुरक्षा योजना

यह योजना मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल जो सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसमें यदि कोई महिला अपना प्रसव करवाती है और यदि वह ग्रामीण क्षेत्र है तो 1400रु. की सहायता प्रदान की जाती है। और यदि शहरी क्षेत्र की कोई महिला अपना प्रसव उर्पयुक्त वर्णित अस्पताल में करवाती है तो 1000रू. दिए जाते हैं तथा साथ ही प्रेरक को भी यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में हैं दोस्त को 350रु. तथा यदि व शहरी क्षेत्र में तो 200रु. दिए जाते हैं।[10]

संचालित योजनाओं का समाज पर प्रभाव

मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह जानने लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य किया गया है। जिसमें 50 लोगों से कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे गये जिनके आधार पर सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ को धरातल पर परखने की कोशिश की गई है। ऑनलाइन सर्वेक्षण कार्य में जो परिणाम आये है उनका मूल्यॉकन निम्नलिखत है–

प्र. 01: आपके परिवार की प्रकृति क्या/कैसी है?

उ. 01: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति "संयुक्त" है। तथा वही 45 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति "एंकाकी" है। और वही 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की प्रकृति "अन्य" है।

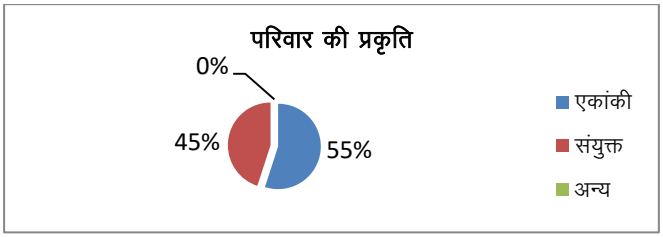

चित्र 01

प्र. 02: आपके परिवार की आवास की स्थिति कैसी है?

उ. 02: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर "पक्का" है। तथा वही 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर "किराये" का है। वही 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनके परिवार की आवास की स्थिति में उनका घर "कच्चा घर, सरकार द्वारा आवास योजना के अर्न्तगत, रिश्तेदारो या सगेसम्बन्धियों, का है।

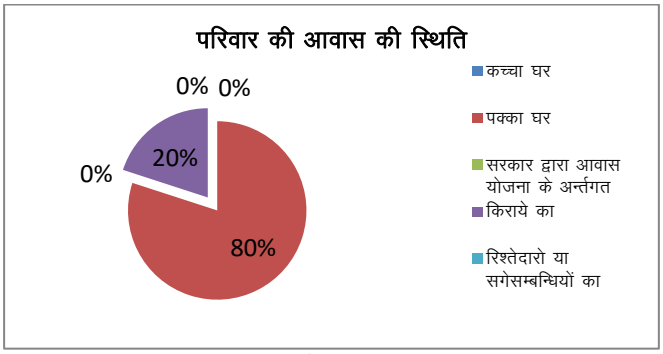

चित्र 02

प्र. 03: क्या आपको शासकीय योजनाओं के बारे मे कोई जानकारी है?

उ. 03: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा "हॉ" में उत्तर दिया गया। तथा वही 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा "नही" में उत्तर दिया गया।

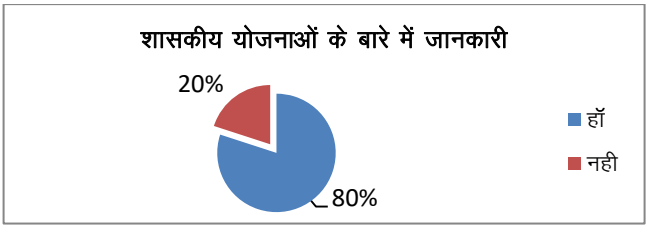

चित्र 03

प्र. 04: आपको कौन सी शासकीय योजनाओं के बारे मे जानकारी है?

उ. 04: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको "आवास योजना" की जानकारी है। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा

कहा गया कि उनको ''चिकित्सीय योजना'' की जानकारी है। 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''शैक्षिक योजना'' की जानकारी है। 00 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''स्वरोजगार योजना'' एवं अन्य योजना की जानकारी है। 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको ''उर्पयुक्त सभी'' योजनाओं की जानकारी है।

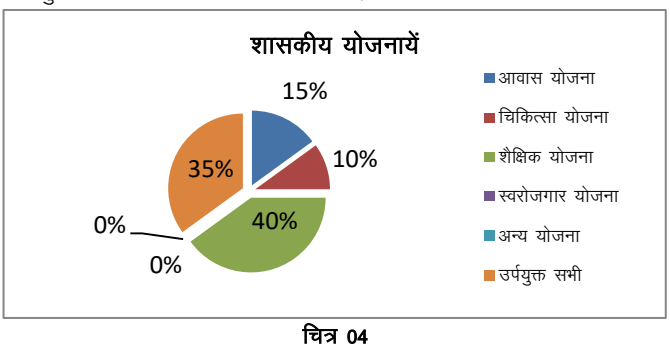

चित्र 04

प्र. 05: आपको शासकीय योजनाओं के बारे मे जानकारी कहॉ से मिलती है?

उ.05: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''शासकीय कर्मचारियों'' द्वारा मिली। 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''एन.जी.ओ.'' द्वारा मिली। 55 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''इन्टरनेट'' द्वारा मिली। 15 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा'' मिली। 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''अन्य प्रकार से'' मिली। 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया कि उनको उनको शासकीय योजनाओं की जानकारी ''किसी के द्वारा नही'' मिली।

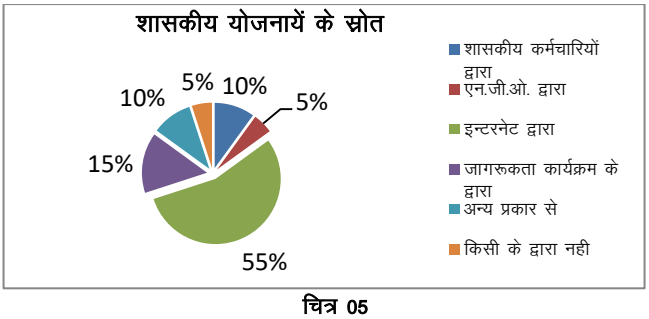

चित्र 05

प्र. 06: आपने कोई शासकीय योजना का लाभ लिया है?

उ. 06: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 05 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''मुझे पता ही नही है'' में उत्तर दिया गया।

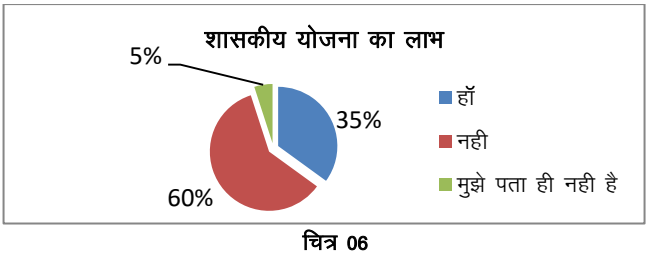

चित्र 06

प्र. 07: क्या आप बता सकते है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है?

उ. 07: उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''हॉ'' में उत्तर दिया गया। वही 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''नही'' में उत्तर दिया गया। और वही 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा ''थोड़ा बहुत'' में उत्तर दिया गया।

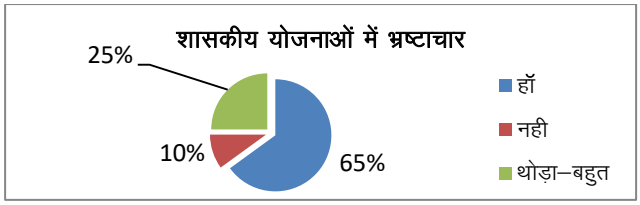

चित्र 07

विवेचन एवं निष्कर्ष

उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि शासकीय योजनाओं का प्रभाव समाज पर सकारात्मक पड़ता है। वही यदि शासकीय योजनाओं का दूसरा पहलू भी देखा जाए तो इन योजनाओं का पर्याप्त रूप से विज्ञापन ना होना जिसकी वजह से लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। और आम जन इनका फायदा नहीं उठा पाते। प्रति वर्ष सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं लाई जाती है और उनको लागू भी किया जाता है लेकिन समाज में जिन लोगों को उनकी आवश्यकता होती है उन तक कई बार जानकारी नही पहुँच पाती है। अधिकांश उनको पता ही नहीं चल पाता कि शासन द्वारा उनके हित के लिए और उनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। और कुछ लोगों को यदि कुछ योजनाओं के बारे में पता भी चल जाता है तो सरकार द्वारा प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया जाता है कि जिससे पात्र व्यक्तियों को भी आसानी से इन योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। सरकारी योजनाओं को पाने के लिए जो प्रक्रिया है वह बहुत ही धीमी गति से होती है, या तो यूं कहें कि सरकार के पास इतने कर्मचारी नहीं होते हैं कि उन्हें तत्काल लागू किया जाए और जिनको आवश्यकता है उन योजनाओं की उनको घर–घर जाकर के उन योजनाओं की जानकारी देकर उनको लाभान्वित किया जा सके। वही दूसरी ओर कुछ उत्तरदाताओं द्वारा कहा गया है कि प्रक्रिया का हवाला देकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा पात्र व्यक्ति से अनचाहा फायदा प्राप्त करने के लिए जानबूझकर पात्र व्यक्ति को उलझाकर रखा जाता है।

सुझाव

1. सरकार को चाहिए कि उनके पास प्रत्येक नगर और शहर की वोटर लिस्ट है। जिसके आधार पर उन लोगों को चिन्हित किया जा सकता है जिनको योजनाओं की आवश्यकता है। उनके नाम पहले से ही घोषित कर दिए जाएं जिससे आवेदन की आवश्यकता ही ना पड़े।
2. सरकार चाहे तो आधार कार्ड के आधार पर भी इसका मूल्यांकन कर सकती है। कौन कौन से व्यक्ति कौन सी योजनाओं के लिए पात्र हैं उनकी सूची जारी कर सकती है।
3. सरकार द्वारा ऐसी कमेटियों या समूहों को बनाया जाए जो समय–समय पर या कुछ अंतरालों में गांवो, नगरों और शहरों का सर्वेक्षण करें और पात्र व्यक्तियों को ढूंढ कर उनकी सूची बनाएं और उन्हें लाभान्वित करें।

संदर्भ सूची

[1] अग्नि सुरक्षा एंव अग्निशमन सेवाऐं: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन: अवलोकन दिनॉक 10/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

[2] सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश: अवलोकन दिनॉक 10/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

[3] वही।

[4] वही।

[5] वही।

[6] वही।

[7] मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन: अवलोकन दिनॉक 10/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

[8] गांव की बेटी योजना: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन: अवलोकन दिनॉक 12/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

[9] प्रतिभा किरण योजना: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन: अवलोकन दिनॉक 12/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

[10] जननी सुरक्षा योजना: सरकारी योजनाएं मध्य प्रदेश शासन: अवलोकन दिनॉक 13/11/20211: https://mp.gov.in/govschemes

****